राज्य (अनुसंधान के माध्यम से) केंद्रीय अन्वेषन ब्यूरो

बनाम

श्री कल्याण सिंह (उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री) और अन्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 751)

अप्रैल 19, 2017

[पिनाकी चंद्र घोस और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

'बाबरी मस्जिद का मामला-मस्जिद को ध्वस्त करना-49 प्राथमिकियां दर्ज की गईं-अपराधों के लिए लाखों कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई पहली प्राथमिकी अंतर्गत आई पी सी धारा, 295,297,332,337,338,395 और 397 आर/डब्ल्यू 120-बी आई पीसी-आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी (जिनमें से दो मर चुके हैं) आईपीसी के तहत, 153-बी, 505 के तहत-इसके अलावा, संज्ञेय अपराधों से संबंधित 46 प्राथमिकियां और गैर-संज्ञेय अपराधों से संबंधित 1 प्राथमिकी भी दर्ज की गई-लखनऊ में दूसरी प्राथमिकी को छोड़कर सभी मामलों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई-विशेष अदालत ने मामलों को सत्र न्यायालय को सौंप दिया-सीबीआई ने एक समेकित आरोप पत्र दायर किया-राज्य सरकार ने अधिसूचना में संशोधन किया और अधिसूचना में संशोधन किया। सभी अपराधों के लिए साक्ष्य लगभग समान हैं और इसलिए इन अपराधों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि 49 अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं-उच्च न्यायालय को अपने फैसले के वितरण के बाद अधिसूचना में सुधार की उम्मीद थी, जिसमें संयुक्त मुकदमा आगे बढ़ता, हालांकि, इसके बजाय, रायबरेली में सीबीआई द्वारा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसने संयुक्त मुकदमे की परिकल्पना को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया-इसलिए, वर्तमान मामले में सबसे अच्छा तरीका

रायबरेली में चल रही कार्यवाही (दूसरी प्राथमिकी) को लखनऊ के सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करना होगा ताकि संयुक्त सुनवाई आगे बढ़ सके।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-'बाबरी मस्जिद' विध्वंस मामला-कार्यवाही को रद्द करना-विशेष अदालत ने 21 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि मस्जिद को ध्वस्त करने वाले अभियुक्तों के दो समूह थे, एक-कार सेवक और अन्य जो उकसाने वाले थे और इसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा-21 अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करना पूरी तरह से गलत था-कहा गया कि अभियुक्तों को संभवतः आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें सीबीआई द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में आपराधिक साजिश के आरोप में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था-आपराधिक साजिश का आरोप पहले से ही संयुक्त आरोप पत्र में है, इस आरोप को 8 अभियुक्तों के समूह के बचे लोगों के खिलाफ पहले से ही बनाए गए आरोपों में जोड़ा जा सकता है-जैसा कि 13 दंड संहिता के अपराधों के समूह के बचे लोगों के खिलाफ किया गया था।

भारत का संविधान- अनुच्छेद 21,142- 'बाबरी मस्जिद' विध्वंस मामला-कार्यवाही का हस्तांतरण-प्रतिवादी संख्या 4,5 ने तर्क दिया कि रायबरेली से लखनऊ में कार्यवाही स्थानांतरित करने के लिए 'आईडी1' का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि रायबरेली में कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास थी और लखनऊ में चल रही कार्यवाही सत्र अदालत के पास थी-यह अनुरोध किया गया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सत्र अदालत में प्रतिवादियों की अपील करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, जिसका उल्लंघन करते हुए 'आईडी2' आयोजित किया गयाः तथ्य यह है कि एक विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट होता है, जबकि दूसरे विशेष न्यायाधीश ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मजिस्ट्रेट से सत्र न्यायालय और सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत लिया जा सकता है, यानी धारा 407 (1) और

(8) के आधार पर-इसलिए, यू/s.407 के तहत भले ही अपील के दो स्तरों को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद.21 का कोई उल्लंघन नहीं है-इसके अलावा, यह तथ्य कि उच्च न्यायालय को Cr.P.C के तहत हस्तांतरण की शक्ति दी गई है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 142-अभिनिर्धारित किया गया : अनुच्छेद 142 द्वारा, समानता को कानून पर प्राथमिकता दी गई है-लेकिन यह उस तरह की समानता नहीं है जो कानून के अनिवार्य मूल प्रावधानों की अवहेलना कर सकती है जब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करता है-राहत देते समय. सर्वोच्च न्यायालय पक्षकारों को कानून के आवेदन में ढील देने या मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारों को कानून की कठोरता से पूरी तरह से छूट देने की सीमा तक जा सकता है-ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है, नहीं, कर्तव्य है कि वह किसी मामले में पूर्ण न्याय करे जब आवश्यक पाया जाए-समानता।

विलंब/ विलंब-'बाबरी मस्जिद' विध्वंस मामला-कथित अपराध जिसने भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को हिला दिया था, लगभग 25 साल पहले किया गया था-अभियुक्त व्यक्तियों को अभी तक कानून के दायरे में नहीं लाया गया है-आयोजितः न्यायाधीश का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। पूरे मुकदमे के समाप्त होने तक मुकदमा चलाना-मामले को किसी भी आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जब सत्र न्यायालय को उस विशेष तिथि के लिए मुकदमा चलाना असंभव लगे, तो उसके लिए कारण दर्ज किए जाएं-सीबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबूत के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह मौजूद रहें, ताकि गवाहों के अभाव में मामला स्थगित न हो-सत्र अदालत मुकदमे को पूरा करे और इस फैसले की प्राप्ति की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर फैसला सुनाए।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 फरवरी, 2001 के फैसले में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सीबीआई द्वारा इस आधार पर एक संयुक्त आरोप पत्र दायर किया गया था कि सभी अपराध कथित साजिश को पूरा करने के लिए एक ही लेन-देन के दौरान किए गए थे। इन सभी अपराधों के लिए साक्ष्य लगभग समान हैं और इसलिए, इन अपराधों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि 49 अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। यह स्पष्ट है कि इसके विपरीत, उच्च न्यायालय का 22 मई, 2010 का विवादित निर्णय, जिसने विशेष न्यायालय के 4 मई, 2001 के फैसले को बरकरार रखा, स्पष्ट रूप से गलत है। आपराधिक साजिश का अपराध पहले से ही सभी नामित अभियुक्तों के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में है, जिसमें 21 अभियुक्त ए शामिल हैं जिन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया है। मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्तों को संभवतः आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जहां तक आपराधिक साजिश के आरोप का संबंध है, उन्हें पहले से ही अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे लखनऊ के विशेष न्यायाधीश द्वारा पहली प्राथमिकी में बताए गए अपराधों से निपटने के दौरान देखा जाएगा। इस संबंध में भी, इसके विपरीत ठहराने में विवादित निर्णय सही नहीं है-[पैरा 14] [963-ए-डी]

2. विवादित निर्णय ने अपराधों और अपराधियों को भी कृत्रिम रूप से दो समूहों में विभाजित किया जो 12 फरवरी, 2001 के फैसले का पालन नहीं करते थे। 12 फरवरी, 2001 के फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को उम्मीद थी कि अधिसूचना (संयुक्त परीक्षण के लिए) में पाया गया दोष निर्णय देने के तुरंत बाद ठीक हो जाएगा, जिस मामले में एक संयुक्त परीक्षण आगे बढ़ेगा। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सी. बी. आई. ने तकनीकी दोष को ठीक करने के अनुरोध की अस्वीकृति को चुनौती नहीं दी। इसके बजाय सी. बी. आई. द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम ने बहुत भ्रम पैदा किया है। रायबरेली में अलग-अलग चल रहे 8 अभियुक्त व्यक्तियों के

खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने और 12 फरवरी, 2001 के फैसले के बाद 13 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह से हटाने से परिकल्पना की गई संयुक्त सुनवाई पूरी तरह से पटरी से उतर गई है और इसके परिणामस्वरूप स्वयं सी. बी. आई. द्वारा दायर एक संयुक्त आरोप पत्र के आधार पर एक साथ दो स्थानों पर खंडित अभियोजन चल रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 फरवरी, 2001 के निर्णय में बताए गए तकनीकी दोष को दूर करके 2001 में राज्य सरकार द्वारा जो किया जाना चाहिए था, उसे दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रायबरेली में चल रही कार्यवाही को लखनऊ के सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करना होगा ताकि नामित व्यक्तियों के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में उल्लिखित सभी अपराधों की संयुक्त सुनवाई आगे बढ़ सके। चूंकि सभी 21 अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप पहले से ही लखनऊ में सीबीआई द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में है, इसलिए इस आरोप को 8 अभियुक्तों के समूह के बचे लोगों के खिलाफ पहले से बनाए गए आरोपों में जोड़ा जा सकता है। 13 के समूह के बचे लोगों के खिलाफ, संयुक्त आरोप पत्र में उल्लिखित दंड संहिता के अपराधों को भी जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, नए सिरे से मुकदमे की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी 21 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उपरोक्त आरोपों को चल रहे मुकदमे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत आसानी से जोड़ा जा सकता है। अभियुक्त पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जाएगा क्योंकि उन्हें जिरह के उद्देश्य से रायबरेली या लखनऊ में पहले से ही जांचे गए गवाहों को वापस बुलाने का अधिकार है। लखनऊ में सत्र न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 217 (ए) का उचित सम्मान करेगा ताकि वापस बुलाने के अधिकार का प्रयोग इस तरह से न किया जाए कि मुकदमा अनुचित रूप से आगे बढ़े। [पैरा 15,16) [963-ई; 964-बी-जी)

3.1 लैटिन उक्ति फिएट जस्टिटिया रुआट सेलम वह है जो अनुच्छेद 142 के पढ़ने पर सबसे पहले दिमाग में आता है-न्याय किया जाए, भले ही आकाश गिर जाए।

यह अनुच्छेद न्यायालय के समक्ष पक्षों को पूर्ण न्याय करने की बहुत व्यापक शक्ति देता है, एक ऐसी शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद है क्योंकि इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंततः पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को समाप्त कर देगा। अनुच्छेद 142 संविधान के अनुच्छेद 141 का अनुसरण करता है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय के दो घटक होते हैं-घोषित कानून जो व्यक्तियों के बीच भविष्य में मुकदमेबाजी में न्यायालयों को बाध्य करता है, और किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करना जो उसके समक्ष लंबित है। वास्तव में, यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो अपने शीर्ष पर इक्विटी के अधिकतम मानकों में से एक को बदल देता है, अर्थात्, इक्विटी कानून का पालन करती है। अनुच्छेद 142 द्वारा समानता को कानून से अधिक प्राथमिकता दी गई है। लेकिन यह उस तरह की समानता नहीं है जो कानून के अनिवार्य मूल प्रावधानों की अवहेलना कर सकती है जब न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करता है। राहत देते समय, न्यायालय पक्षकारों को कानून लागू करने में ढील देने या मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारों को कानून की कठोरता से पूरी तरह से छूट देने की सीमा तक जा सकता है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के पास शक्ति है, नहीं, कर्तव्य है कि वह आवश्यक पाए जाने पर किसी मामले में पूर्ण न्याय करे। वर्तमान मामले में, भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को हिलाने वाले अपराध कथित रूप से लगभग 25 साल पहले किए गए हैं। अभियुक्त व्यक्तियों को मुख्य रूप से एक संयुक्त मुकदमे में उपरोक्त कथित अपराधियों के अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाने में सी. बी. आई. के आचरण और तकनीकी दोषों के कारण कानून के दायरे में नहीं लाया गया है, जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता था, लेकिन जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ठीक नहीं किया गया था। [पैरा 19) [966-एफ-जी; 967-ए-ई]

3.2 वर्तमान मामले में, स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग एक विशेष न्यायाधीश से दूसरे विशेष न्यायाधीश को मामला स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है, न कि उच्च न्यायालय को। तथ्य यह है कि एक विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट होता है, जबकि दूसरे विशेष न्यायाधीश ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट से सत्र न्यायालय और सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत लिया जा सकता है, यानी धारा 407 (1) और (8) के आधार पर, यदि मामले को रायबरेली के मजिस्ट्रेट से ही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए, धारा 407 के तहत, भले ही अपील के दो स्तरों को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि धारा 407 (1) (iv) को धारा 407 (8) के साथ पढ़ने पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाता है। [पैरा 24] [969-बी-डी]

4. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैंः i) कार्यवाही। रायबरेली में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दूसरी प्राथमिकी लखनऊ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अयोध्या मामले) की अदालत में स्थानांतरित कर दी जाएगी; 2) सत्र न्यायालय 6 अभियुक्तों के खिलाफ धारा 120-बी के तहत अतिरिक्त आरोप तय करेगा। सत्र न्यायालय 6 अभियुक्तों के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में उल्लिखित दंड संहिता की धारा 120-बी और अन्य प्रावधानों के तहत अतिरिक्त आरोप तय करेगा। एक अभियुक्त, राजस्थान का राज्यपाल होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत प्रतिरक्षा का हकदार है जब तक कि वह राजस्थान का राज्यपाल रहता है। सत्र न्यायालय उनके राज्यपाल के पद से हटते ही उनके खिलाफ आरोप तय करेगा और उनके खिलाफ कदम उठाएगा; 3) सत्र न्यायालय, रायबरेली से लखनऊ में कार्यवाही स्थानांतरित करने और अतिरिक्त आरोप तय करने के बाद, चार सप्ताह के भीतर, सभी मामलों को उस स्तर से दिन-प्रतिदिन के आधार पर उठाएगा, जिस स्तर पर रायबरेली और लखनऊ दोनों में मुकदमे की कार्यवाही चल

रही है, जब तक कि मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता। कोई नया परीक्षण नहीं होगा। जब तक पूरा मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता तब तक मुकदमे का संचालन करने वाले न्यायाधीश का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। मामला किसी भी आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि जब सत्र न्यायालय को उस विशेष तिथि के लिए मुकदमा चलाना असंभव लगे। ऐसी स्थिति में, अगले दिन या निकटवर्ती तिथि के लिए स्थगन के अनुदान पर, इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

iv) सी. बी. आई. यह सुनिश्चित करेगी कि साक्ष्य के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह उपस्थित रहें, ताकि गवाहों की कमी के कारण मामला स्थगित न हो; v) सत्र न्यायालय मुकदमा पूरा करेगा और इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर निर्णय देगा। [पैरा 27) [972-जी-एच; 973-ए-जी]

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और एक अन्य (1988) 2 एस. सी. सी. 602: (1988) 1 पूरक। एस. सी. आर. 1-लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य 1998 (4) एस. सी. सी. 409: [1998) 2 एस. सी. आर. 795; पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (2014) 8 एस. सी. सी. 883: [2014) 8 एस. सी. आर. 228। संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1988) 1 पूरक एस. सी. आर. 1 (1998) 2 एस. सी. आर. 795 (2014) 8 एस. सी. आर. 228 अभिनिर्धारित. पैरा 13 पैरा 18 पैरा 18 को संदर्भित लागू करने योग्य

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2017 की आपराधिक अपील संख्या 751

2001 के आपराधिक संशोधन सं. 217 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक से।

एन. के. कौल, ए. एस. जी., सुश्री वी. मोहना, के. के. वेणुगोपाल, विक्रमजीत बनर्जी, कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजीव नंदा, एस. एस. कचवाहा, सन्यात लोढ़ा, रितिन राय, नीतेश दरयानानी, अनुपम मिश्रा, सुश्री चानन परवानी, हरीश कुमार, मुकेश कुमार मरोरिया, मेरुसागर सामंताराय, डी. भरत कुमार, भास्कर गौतम, सुश्री लिंगनेवा, सुश्री विदुषी, अंकुर तलवार, संतोष कुमार, भरत सूद, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री कामिनी जैसवाल, एम. आर. शमशाद, फारुख रशीद, आदित्य समद्दर, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा दिया गया था।

अनुमति प्रदान की गई

1. वर्तमान अपील बाबरी मस्जिद के विध्वंस से उत्पन्न होती है। हम इस मामले में 6 दिसंबर, 199 जेड को दर्ज की गई दो प्राथमिकियों से चिंतित हैंः पहला अर्थात। अपराध (आई. डी. 1), लाखों कार सेवकों के खिलाफ है, जो डकैती, डकैती, चोट पहुँचाने, सार्वजनिक पूजा स्थलों को घायल करने/अपवित्र करने, धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने आदि के अपराधों का आरोप लगाते हैं। इसलिए आई.पी. सी. अपराध धारा 153-ए, 295,297,332,337,338,395 और 397 के तहत थे। दूसरी एफ. आई. आर.। 1992 का एफ. एल. आर. No.198 उसमें नामित आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था-श्री. एल. के. आडवाणी, श्री अशोक सिंघल, श्री विनय कटियार, सुश्री उमा भारती, सुश्री साध्वी ऋतंबरा, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री गिरिराज किशोर और श्री विष्णु हरि डालमिया, जिनमें से दो का समय बीतने के कारण निधन हो गया है। श्री अशोक सिंघल और श्री गिरिराज किशोर। एफ. आई. आर. में आई. पी. सी. की धारा 153-ए, 153-बी और धारा 505 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है। संज्ञेय अपराधों से संबंधित 46 और प्राथमिकियां और गैर-संज्ञेय अपराधों से संबंधित 1 प्राथमिकियां भी दर्ज की गईं। शुरू में, ललितपुर में एक विशेष

अदालत का गठन इन मामलों की सुनवाई करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में अधिसूचना जारी की गई। राज्य सरकार ने 8 सितंबर, 1993 को उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद इन मामलों की सुनवाई लखनऊ में एक विशेष न्यायालय द्वारा की जानी थी। ये सभी मामले लखनऊ के सत्र न्यायालय को सौंपे गए थे, जिसमें एफ. आई. आर. No.197, लेकिन FIR.No.198 नहीं, पर मुकदमा चलाया जाना था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 13 अप्रैल, 1993 के एक आदेश द्वारा लखनऊ को 1992 की एफ. आई. आर. संख्या 197 के हस्तांतरण से पहले, विशेष मजिस्ट्रेट ने 1992 की उक्त एफ. आई. आर. No.197 में आई. पी. सी. की धारा पी. 120-बी. को जोड़ा था।

2. 5 अक्टूबर, 1993 को सी. बी. आई. ने श्री बाला साहेब ठाकरे, श्री कल्याण सिंह, श्री मोरेश्वर सावे, श्री चंपत राय बंसल, श्री सतीश प्रधान, श्री महंत अवैद्यनाथ, श्री धरम दास, श्री महंत नृत्य गोपाल दास, श्री महामादलेश्वर जगदीश मुनि, श्री राम बी लास वडंती, श्री वैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम , श्री प्रम हंस राम चंद्र दास और डी सतीश चंद्र नगर सहित सभी 48 व्यक्तियों के खिलाफ एक समेकित आरोप पत्र दायर किया। यह कहा जा सकता है कि समय बीतने के कारण इनमें से छह की मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम श्री बाला साहेब ठाकरे, श्री मोरेश्वर सावे, श्री महंत हैं। श्री अवैद्यनाथ, श्री प्रम हंस रामचंद्र दास, श्री महामंडलेश्वर जगदीश मुनि और डॉ. सतीश नागर। जहाँ तक साजिश के आरोप का संबंध है, आरोप पत्र में लिखा हैः

उपरोक्त कार्य शिवसेना, बॉम्बे के प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे, श्री एल. के. अदितनी, सांसद, भाजपा, वर्तमान भाजपा अध्यक्ष, श्री कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री अशोक सिंघल, महासचिव, विहिप, श्री विनय कटियार, सांसद बजरंग दल, श्री मोरेश्वर सावे, सांसद, शिवसेना, श्री पवन कुमार पांडे, पूर्व विधायक, शिवसेना, श्री बृजभूषण सरन सिंह, सांसद, भाजपा, श्री जय भगवान गोयल, उत्तर भारत प्रमुख, शिवसेना, सुश्री उमा भारती @गजरा सिंह, सांसद, भाजपा, साध्वी ऋतंभरा, विहिप नेता,

महाराज स्वामी साक्षी, सांसद, भाजपा, श्री सतीश प्रधान, सांसद, शिवसेना, श्री मुरली मनोहर , भाजपा कार्यकर्ता श्री रमेश प्रताप सिंह और बजरंग दल के नेता आचार्य धर्मेंद्र देव ने आई. पी. सी. की धारा 153-ए, 295,295-ए और 505 और आई. पी. सी. की धारा 153-ए, 295,295-ए और 505 के तहत अपराधों का गठन किया है।

3. 8 अक्टूबर, 1993 को राज्य सरकार ने 9 सितंबर, 1993 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए उपरोक्त आठ व्यक्तियों के खिलाफ 1992 की प्राथमिकी दर्ज की ताकि सभी 49 मामलों की सुनवाई विशेष अदालत, लखनऊ द्वारा की जा सके। एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए, क्योंकि यह संशोधन अधिसूचना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 (1) के प्रावधान का पालन नहीं करती थी, यानी कि उच्च न्यायालय के साथ परामर्श की कमी थी, इस अधिसूचना को अंततः रद्द कर दिया गया था।

4. इस बिंदु पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सी. बी. आई. ने वर्ष 1996 में लखनऊ में उपरोक्त 8 व्यक्तियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। 9 सितंबर, 1997 को लखनऊ के विशेष न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न अन्य धाराओं के साथ पठित धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए सभी ए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी अपराध एक ही लेन-देन के दौरान किए गए थे, जिसके लिए एक संयुक्त परीक्षण की आवश्यकता थी और यह मामला विशेष रूप से विशेष न्यायाधीश, लखनऊ की अदालत द्वारा विचारणीय था। इस क्रम के कुछ हिस्सों को निर्धारित करना उचित है जो इस प्रकार हैंः

"आरोपी श्री लाल कृष्ण, अशोक सिंह, विनय कटियार, मोरेश्वर सावे, पवन कुमार पांडे, सुश्री साध्वी ऋतंभरा, महाराज स्वामी साक्षी, मुरली मनोहर जोशी, ओरी

राज किशोर और विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 147,153-ए/153-बी/ए/505 के तहत अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। आरोपी पवन कुमार पांडे, बृज भूषण, सरन सिंह, पवैया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, राम नारायण दास, लल्लू सिंह, ओम प्रकाश पांडे, लक्ष्मी नारायण दास, महा त्यागी, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, हर गोविंद सिंह, विजय बहादुर सिंह, नवीन भाई शुक्ला के खिलाफ अपराध, आईपीसी की धारा 332/338/2-01 के तहत <ID1 के साथ पढ़े जाने वाले अपराध प्रतीत होते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार आई. पी. सी. की धारा 153-ए/153-बी/295/295-ए/505 के साथ पठित आई. पी. सी. की <आई. डी. 1 के तहत श्री बाला साहेब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, विनय कटियार, मोरेश्वर सावे, पवन कुमार पांडे, बृजभूषण सरन सिंह, जय भगवान गोल, महाराज स्वामी साक्षी, सतीश प्रधान, मुरली मनोहर जोशी, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विनोद कुमार वत्स, रामचंद्र खत्री, सुधीर सिंह पाव्या, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, राम नारायण दास, रामजी गुप्ता, लल्लू सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध किए गए प्रतीत होते हैं।

जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत साजिश के सवाल का संबंध है, उस संबंध में सबूत साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक साजिश गुप्त रूप से रची जाती है और इस साजिश का ज्ञान धीरे-धीरे शेष अभियुक्तों के पास आता है और यह ज्ञान उनके भाषणों और उनके द्वारा किए गए कार्यों से स्पष्ट होता है। आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केहर सिंह बनाम दिल्ली राज्य 1988 एस. सी. सी. (आपराधिक) 711 के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में प्रस्ताव किया गया है, जहां किसी भी साजिश के कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे गए हैं जो वह नहीं करता है और किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जानकारी नहीं है जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो जाता है। इस तरह की साजिश में सभी व्यक्ति जो इससे जुड़े हैं, उन्हें साजिश के कारण गैरकानूनी रूप से

की गई गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उन सभी ने उस तरह से कार्य करने का निर्णय लिया है जैसा कि निम्नलिखित मामलों में निर्णय द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

(1) अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ-1993 एस. सी. सी. (आपराधिक) पृष्ठ 961

(2) पी. के. नारायण बनाम केरल राज्य-(1995) एस. सी. सी. 142

(3) महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापर-1996

उपरोक्त माननीया उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, यद्यपि घटना के समय श्री कल्याण सिंह या अभियुक्त आर. एन. श्रीवास्तव और श्री डी. बी. राय उपस्थित नहीं थे, फिर भी उन्हें आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है क्योंकि वे लोक सेवक हैं, उनका कार्य प्रथम दृष्टया आपराधिक माना जाएगा। श्री कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय एकता परिषद के समक्ष विवादित ढांचे को ध्वस्त नहीं करने का आश्वासन दिया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल प्रतीकात्मक कार सेवा की अनुमति दी थी। श्री कल्याण सिंह ने यह भी कहा था कि वह राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद संरचना की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे और इसे गिराया नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासनों के विरोध में काम किया। श्री कल्याण सिंह द्वारा केंद्रीय बल का उपयोग करने का आदेश नहीं दिया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश में एक आवश्यक भागीदार था।

उपरोक्त मामलों में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव दिया है कि यदि घटना के एक क्रम में अलग-अलग अभियुक्तों द्वारा अलग-अलग अपराध किए जाते हैं तो उनकी जांच संयुक्त रूप से की जा सकती है। वर्तमान मामले में राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद संरचना को गिराए जाने के संबंध में आपराधिक साजिश को ध्यान में रखते हुए और उस संदर्भ में जो भी कार्य किए गए हैं, उन्हें एक घटना के दौरान किया गया माना जाएगा। आई. पी. सी. की धारा 395 बाबरी मस्जिद को गिराए

जाने की आपराधिक साजिश के बारे में भी थी। यह आई. पी. सी. के तहत किया गया था जो एक घटना के दौरान है और उस संबंध में पी. डब्ल्यू.-37 संजय खरे, पी. डब्ल्यू.-112 मोहन सहाय, पी. डब्ल्यू.-16 ओम मेहता, पी. डब्ल्यू.-42 प्रवीण जैन के साक्ष्य हैं और पी. डब्ल्यू.-38 शारदा चंद्र प्रधान के बयान जैसे पत्रकारों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में कहा गया है कि जब दोपहर 1:30 बजे तक कार सेवक ऊपर से गुंबद को ध्वस्त नहीं कर सके, तो वे नीचे से दीवारों को ध्वस्त कर रहे थे और विनय कटियार और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल ने कई बार प्रोत्साहित किया कि सभी व्यक्तियों को गुंबद से नीचे उतरना चाहिए क्योंकि यह गिरने की स्थिति में था। यह पीडब्लू-145 सुश्री लतिका गुप्ता का बयान है कि श्री आडवाणी ने यह घोषणा की थी कि सी. आर. पी.एफ किसी भी समय आ सकता है और इसलिए सभी को जाना चाहिए और इसे आने से रोकने के लिए सड़क को अवरुद्ध करना चाहिए। श्रीमती. विजय राजे सिंधिया ने कारसेवकों को नीचे आने के लिए भी कहा जब गुंबद को गिराया जा रहा था और मंच पर मिठाई बांटी जा रही थी

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान मामले में राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने की आपराधिक साजिश आरोपी द्वारा 1990 से शुरू की गई थी और इसे श्री लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य लोगों द्वारा अलग-अलग समय पर पूरा किया गया था और विभिन्न स्थानों पर उपरोक्त विवादित ढांचे को ध्वस्त करने की आपराधिक साजिश की योजनाएं बनाई गई थीं। इसलिए मुझे प्रथम दृष्टया अभियुक्त एस/श्री बाला साहेब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, विनय कटियार, मोरेश्वर सावे, पवन कुमार पांडे, बृज भूषण सरन सिंह, जय भगवान गो, सुश्री उमा भारती, सुश्री साध्वी ऋतंभरा, महाराज सरनी साक्षी, मुरली मनोहर जोशी, गिरि राज किशोर विष्णु हरि डालमिया, चमपत राय बंसल, ओम प्रकाश पांडे, सतीश प्रधान अवैध नाथ, भारत दास, महंत नृत्य गोपाल दास, महा मंडलेश्वर जगदीश मुनि, डॉ. राम विलास वेदांती, वैकुंठ लाल शर्मा @प्रेम

हंस राम चंद्र दास पर आरोप लगाने के लिए सबूतों के बल पर आधार मिलता है। विजय राजे सिंधिया और डॉ. सतीश कुमार नागर आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा ए/153-बी/295-ए/505 के तहत अपराधों के लिए।

5. 9 सितंबर, 1997 के आदेश के खिलाफ आपराधिक संशोधन याचिकाएं दायर की गईं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 12 फरवरी, 200। को दिए गए एक निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

(।) 9 सितंबर, 1993 की अधिसूचना में संशोधन करने वाली 8 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना अमान्य थी क्योंकि उक्त अधिसूचना जारी करने से पहले उच्च न्यायालय के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक इलाज योग्य कानूनी दुर्बलता थी

(2) नतीजतन, लखनऊ के विशेष न्यायालय के पास 1992 के सत्र न्यायालय की एफ. आई. आर. में उल्लिखित तीन अपराधों के लिए उपरोक्त आठ अभियुक्तों के खिलाफ जांच करने और उन्हें प्रतिबद्ध करने के लिए कोई न्यायपालिका नहीं है।

(3) धारा । 53-ए, । 53-बी और 505 एल. पी. सी. के तहत आरोप तय करने के लिए 9 सितंबर, । 997 का विवादित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इस हद तक खारिज किया जा सकता था।

(4) एक संयुक्त आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए निम्न न्यायालय द्वारा इस आधार पर कोई अवैधता नहीं की गई थी कि सभी अपराध एक ही लेन-देन के दौरान और एक आपराधिक साजिश को पूरा करने के लिए किए गए थे। सभी अपराधों के लिए साक्ष्य लगभग समान हैं और इसलिए, इन तथ्यों के बावजूद कि 49 अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं, इन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

(5) आपराधिक षड्यंत्र और गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य से संबंधित अपराध प्रथम दृष्टया बनाए गए हैं और चूंकि इन अपराधों को एक ही लेन-देन के दौरान किए

जाने का आरोप लगाया गया है, इसलिए विशेष न्यायालय ने उचित रूप से इसका संज्ञान लिया और इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

(6) अन्य सभी मामलों में, जहां तक 49 मामलों में से 48 मामलों का संबंध है, आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए आरोप तय करने के लिए 9 सितंबर, 1997 के विवादित आदेश को अन्य अपराधों के साथ पढ़ा जाता है, सिवाय तीन अपराधों को छोड़कर! उपरोक्त आठ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को बरकरार रखा गया था।

6. सी. बी. आई. ने उपरोक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से 16 जून, 2001 को 8 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना में दोष को सुधारने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 28 सितंबर, 2002 को दोष को ठीक करने के उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति को सी. बी. आई. द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

7. इस बीच एक एसएलपी मोहम्मद द्वारा दायर की गई थी। असलम उर्फ भुरे, एक जनहित याचिकाकर्ता, ने 12 फरवरी, 2001 के आदेश को चुनौती दी। इसे इस न्यायालय द्वारा 29 नवंबर, 2002 को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ समीक्षा को 22 मार्च, 2007 के एक बोलने वाले आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 12 फरवरी, 2008 को एक सुधारात्मक याचिका भी खारिज कर दी गई।

8. इससे यह देखा जा सकता है कि 12 फरवरी, 2001 का आदेश अंतिम है और इसे न्यायिक निर्णय माना जा सकता है। यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना में दोष को दूर करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, सी. बी. आई. ने अस्वीकृति को चुनौती देने के बजाय रायबरेली में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आई. पी. सी. की धारा 153 ए, 153 बी, 505 के साथ धारा 147

और 149 के तहत अपराधों के लिए 8 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। उक्त अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ इन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। जहां तक 13 व्यक्तियों का दूसरा समूह शामिल है, फिर से, सी. बी. आई. को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, सी. बी. आई. ने उनके खिलाफ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की।

9. 4 मई, 2001 के एक आदेश द्वारा, विशेष न्यायालय ने 21 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया। आठ अभियुक्त व्यक्तियों में श्री एल. के. आडवाणी, श्री अशोक सिंघल (मृतक), श्री विनय कटियार, सुश्री उमा भारती, सुश्री साध्वी ऋतंभरा, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री गिरिराज किशोर (मृतक), श्री विष्णु हरि डालमिया और 13 अभियुक्त व्यक्तियों में श्री बाला साहेब ठाकरे (मृत), श्री कल्याण सिंह, श्री मोरेश्वर सेव (मृत), श्री चंपत राय बंसल, श्री सतीश प्रधान, श्री महंत अवैध्यनाथ (मृत), श्री धरम दास, श्री महांत नृत्य गोपाल दास, श्री महामादलेश्वर जगदीश मुनि, श्री राम बिलास वडंती शामिल हैं। न्यायालय ने सोचा कि उसके सामने दो विकल्प थे, और इन 21 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ने का एक कम विकल्प चुना ताकि कारसेवकों के खिलाफ कार्यवाही जारी रह सके। 4 मई, 2001 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण दायर किया गया था और जिसके कारण 22 मई, 2010 का विवादित निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय ने 4 मई, 2001 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्तों के दो वर्ग थे, अर्थात्, मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर कारसेवकों को प्रोत्साहित करने वाले नेता और स्वयं कार सेवक। दोनों के खिलाफ आरोपों की प्रकृति अलग थी और उनकी संलिप्तता अलग-अलग आपराधिक अपराधों के लिए थी। सी. बी. आई. की ओर से यह निवेदन कि निचली अदालत अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपमुक्त नहीं कर सकती थी क्योंकि यह 9 सितंबर, 1997 के आदेश की समीक्षा के बराबर होगा, को अस्वीकार कर दिया गया था। सी. बी. आई. ने यह भी याचिका दायर की कि आई. पी. सी. की धारा

153ए, 153बी और 505 से संबंधित 3 अपराधों और 3 अपराधों के संबंध में अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिबंध केवल 8 व्यक्तियों के खिलाफ था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1992 की एफ. आई. आर. No.198 में दर्ज पूरे अपराध में उल्लिखित 3 धाराओं के अलावा अन्य धाराएं शामिल होंगी और इसलिए इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। विवादित फैसले के अनुसार, उपरोक्त 8 या 13 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश कभी नहीं रची गई क्योंकि अन्यथा रायबरेली में सी. बी. आई. द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में धारा 120 बी शामिल होती जो उसने नहीं की थी। सी. बी. आई. की इस दलील को खारिज करते हुए कि 12 फरवरी, 2001 के फैसले में इस आधार पर एक संयुक्त आरोप पत्र दायर किया गया था कि एक ही लेन-देन के दौरान अलग-अलग अपराध किए गए थे, और एक याचिका कि एक प्रथम दृष्टया मामला साजिश से बनाया गया था, इस तथ्य के साथ कि 9 सितंबर, 1997 का आदेश बरकरार है, अन्य सभी अभियुक्तों को भी आक्षेपित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया थाः

> "अन्यथा भी 1992 के अपराध के अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 153-ए, 153-बी और 505 के संबंध में साजिश के आरोप/आरोप (आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत) का कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्रतीत नहीं होता है जब आई. पी. सी. की धारा 147 और 149 पहले ही जोड़ी जा चुकी हैं।
>
> इसी तरह अगर आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का आरोप आठ मुख्य नेताओं के खिलाफ नहीं लगाया गया है तो बाकी 13-1 = 12 नेताओं के खिलाफ इसे कैसे लागू किया जा सकता है। इन शेष 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप भी वही हैं जो 1992 के अपराध (आईडी1) के दायरे में पाए गए हैं, क्योंकि वे भी उन 8 व्यक्तियों के साथ राम कथा कुंज में एक ही मंच

साझा कर रहे थे। अंत में, इसलिए, इस प्रस्तुतिकरण में भी योग्यता का अभाव है।"

10. यह भी कहा गया कि यदि सी. बी. आई. के पास साजिश का कोई सबूत है तो वह रायबरेली में अदालत के समक्ष एक पूरक आरोप पत्र दायर कर सकती है जिसे 1992 के अपराध से जब्त कर लिया गया था। यह मानते हुए कि घटना के दो अलग-अलग स्थानों और आरोपों की अलग-अलग प्रकृति के कारण शुरू से ही दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं, निर्णय ने तब सीबीआई के सभी 49 प्राथमिकियों के लिए एक संयुक्त आरोप पत्र तैयार करने पर आपत्ति जताई और अंततः पाया कि 4 मई, 2001 के विवादित आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ दायर संशोधन को खारिज कर दिया।

11. सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित अपर सॉलिसिटर जनरल श्री नीरज कौल ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि विवादित फैसले ने 12 फरवरी, 2001 के फैसले की पूरी तरह से गलत व्याख्या की है और 21 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को हटाने की पुष्टि की है जो नहीं किया जा सका। श्री कौल के अनुसार, विभिन्न प्रकार के अपराधों और अपराधियों के बीच विवादित निर्णय द्वारा एक कृत्रिम अंतर किया गया था, जब वास्तव में, 2001 निर्णय ने स्पष्ट रूप से सी. बी. आई. द्वारा संयुक्त आरोप पत्र दाखिल करने को बरकरार रखा था। उन्होंने तर्क दिया कि साजिश का अपराध पहले से ही विशेष अदालत, लखनऊ के समक्ष 1992 की प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों में निहित था और यही कारण था कि रायबरेली में उपरोक्त 8 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र में धारा 120बी आरोप नहीं जोड़ा गया था। यह विवादित फैसले से पूरी तरह चूक गया, जिसमें गलती से कहा गया था कि सी. बी. आई. के लिए रायबरेली में धारा 120 बी का प्रभार जोड़ना संभव था। श्री कौल के अनुसार, यदि ऐसा किया जाता है तो दो अलग-अलग विशेष न्यायालयों को

एक ही आपराधिक साजिश पर निर्णय लेना होगा और उसी के बारे में अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, जो विवादित फैसले में मूल कमजोरी है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त 21 अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी को भी हटा नहीं दिया जाना चाहिए था, और सी. बी. आई. ने 8 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ रायबरेली में एक पूरक आरोप पत्र केवल इसलिए दायर किया था क्योंकि वह उनके खिलाफ मुकदमे को तेजी से समाप्त करना चाहती थी, जो केवल तभी हो सकता था जब उनके खिलाफ रायबरेली में कार्रवाई की जाती, क्योंकि राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना में दोष को ठीक करने से इनकार कर दिया था।

12. प्रतिवादी Nos.4 और 5 की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. के. वेणुगोपाल ने तर्क दिया है कि 12 फरवरी, 2001 के फैसले को इस स्तर पर फिर से नहीं खोला जा सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया है और एक समीक्षा याचिका और एक सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया है। सी. बी. आई. को उपरोक्त फैसले से जो बंद हो गया है, उसे फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, चूंकि 4 मई, 200 आई का आदेश केवल 12 फरवरी, 2001 के फैसले और आदेश को लागू करता है और विवादित फैसले ने 4 मई, 2001 के उक्त फैसले को बरकरार रखा है, इसलिए सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए। चूंकि 8 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा रायबरेली में चल रहा है, इसलिए 12 फरवरी, 2001 के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करने वाले इस अदालत के अंतिम और बाध्यकारी फैसले को देखते हुए लखनऊ में विशेष अदालत के समक्ष संयुक्त मुकदमे का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग उपरोक्त 8 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपरोक्त 8 अभियुक्त

व्यक्तियों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अन्यथा उल्लंघन किया जाएगा क्योंकि विद्वान मजिस्ट्रेट, रायबरेली से सत्र न्यायालय में अपील करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 407 (1) का भी उल्लेख किया जिसके द्वारा यह स्पष्ट था कि एक विशेष न्यायाधीश से एक ही राज्य के भीतर दूसरे विशेष न्यायाधीश को स्थानांतरण का आदेश उपरोक्त प्रावधान के दायरे में आएगा और यह केवल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसमें दोनों निचली अदालतें स्थित हैं। चूंकि अनुच्छेद 142 का उपयोग कानून के मूल प्रावधानों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह धारा 407 (1) का उल्लंघन होगा जो केवल उच्च न्यायालय को इस तरह के मामले को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कई फैसलों का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कानून के अनिवार्य मूल प्रावधान के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

13. श्री कपिल सिब्बल, एस. एल. पी. (सी. आर.) में अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील। No.2705of2015 को हमारे द्वारा एसएलपी याचिकाकर्ता को एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में मानते हुए बहस करने की अनुमति दी गई थी। नतीजतन, उन्होंने हमें केवल कानून के प्रश्नों पर संबोधित किया। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, इस अदालत को रायबरेली में लंबित मामले को लखनऊ स्थानांतरित करना चाहिए क्योंकि 1992 की एफ. आई. आर. No.198 सहित सभी 49 एफ. आई. आर. को मिलाकर एक संयुक्त आरोप पत्र दायर किया गया है। इस न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत इस अत्यंत व्यापक शक्ति का उपयोग करने से कुछ भी नहीं रोक सका। उन्होंने आगे बताया कि ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्य (1988) 2 एस. सी. सी. 602 के फैसले पर कोई भी निर्भरता गलत होगी क्योंकि उक्त निर्णय पूरी तरह से अलग था। उनके अनुसार, संहिता की धारा 216 और 223 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि मुकदमे को नए सिरे से शुरू करने की

आवश्यकता नहीं है, लेकिन रायबरेली और लखनऊ दोनों में जिन गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, उन्हें उन आरोपों पर जिरह के सीमित उद्देश्य के लिए वापस बुलाया जा सकता है जिन्हें अब जोड़ा जाना है।

14. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। हमारा विचार है कि 12 फरवरी, 2001 के फैसले में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीबीआई द्वारा इस आधार पर एक संयुक्त आरोप पत्र दायर किया गया था कि सभी अपराध कथित साजिश को पूरा करने के लिए एक ही लेन-देन के दौरान किए गए थे। इन सभी अपराधों के लिए साक्ष्य लगभग समान हैं और इसलिए, इन अपराधों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, भले ही 49 अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हों। यह स्पष्ट है कि इसके विपरीत, विवादित निर्णय, जिसने 4 मई, 2001 के फैसले को बरकरार रखा, स्पष्ट रूप से गलत है। इसके अलावा, हम श्री नीरज कौल से सहमत हैं कि सभी नामित अभियुक्तों के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में आपराधिक साजिश का अपराध पहले से ही है, जिसमें 21 अभियुक्त शामिल हैं जिन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया है। मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्तों को संभवतः आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जहां तक आपराधिक साजिश के आरोप का संबंध है, उन्हें पहले से ही अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे विशेष न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा 1992 की एफ. आई. आर. No.197 में किए गए अपराधों से निपटने के दौरान देखा जाएगा। इस संबंध में भी, हमारा विचार है कि इसके विपरीत ठहराने में विवादित निर्णय सही नहीं है।

15. आक्षेपित निर्णय ने अपराधों और अपराधियों को भी कृत्रिम रूप से दो समूहों में विभाजित किया जो 12 फरवरी, 2001 के फैसले का पालन नहीं करते थे। इसके विपरीत, उक्त निर्णय ने संयुक्त आरोप पत्र को बरकरार रखते हुए और प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश का मामला सामने आने पर, इसे उक्त निर्णय के विपरीत नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा, विवादित निर्णय अपने आप में विरोधाभासी है

जब यह कहता है कि 21 अभियुक्त व्यक्ति कई स्थानों पर एक समूह बनाते हैं, जबकि उसके पैराग्राफ 31 में उसी निर्णय ने स्पष्ट रूप से 8 अभियुक्तों और 13 अभियुक्तों के दूसरे समूह के बीच अंतर किया है। उसने आगे कहाः

> "सी. बी. आई. की ओर से एक अन्य दलील यह है कि एस/श्री बाला साहेब ठाकरे, कल्याण सिंह और सतीश प्रधान के संबंध में, विद्वत निचली अदालत ने बहुत संक्षिप्त रूप से निपटा है और उन्हें 1992 के अपराध के दायरे में रखने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं। इन अभियुक्तों के संबंध में विद्वत निचली अदालत द्वारा की गई चर्चा सटीक हो सकती है, लेकिन जो निष्कर्ष निकला है वह सही है क्योंकि ये नेता अन्य नेताओं के साथ उक्त मंच पर शारीरिक रूप से भी मौजूद नहीं थे।"

16. उपरोक्त निष्कर्ष कई स्थानों पर विवादित फैसले द्वारा बार-बार कही गई बातों के खिलाफ है, और यह स्पष्ट है कि 13 व्यक्ति अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मंच पर शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। 12 फरवरी, 2001 के फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को उम्मीद थी कि अधिसूचना में पाया गया दोष निर्णय दिए जाने के तुरंत बाद ठीक हो जाएगा. इस मामले में एक संयुक्त सुनवाई आगे बढ़ेगी। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सी. बी. आई. ने इस तकनीकी दोष को ठीक करने के अनुरोध की अस्वीकृति को चुनौती नहीं दी। इसके बजाय सी. बी. आई. द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम ने बहुत भ्रम पैदा किया है। रायबरेली में अलग से चल रहे 8 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने और 12 फरवरी, 2001 के फैसले के बाद 13 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह से हटाने से परिकल्पना की गई संयुक्त सुनवाई पूरी तरह से पटरी से उतर गई है और इसके परिणामस्वरूप स्वयं सी. बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र के आधार पर एक साथ दो स्थानों पर खंडित अभियोजन चल रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय

द्वारा 12 फरवरी, 2001 के निर्णय में बताए गए तकनीकी दोष को दूर करके 2001 में राज्य सरकार द्वारा जो किया जाना चाहिए था, उसे दूर करने के लिए हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में सबसे अच्छा तरीका रायबरेली में चल रही कार्यवाही को लखनऊ के सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करना होगा ताकि नामित व्यक्तियों के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में उल्लिखित सभी अपराधों की संयुक्त सुनवाई आगे बढ़ सके। हमारे विचार में, चूंकि सभी 21 अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप पहले से ही लखनऊ में सी. बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में है, इसलिए इस आरोप को 8 अभियुक्तों के समूह के बचे लोगों के खिलाफ पहले से बनाए गए आरोपों में जोड़ा जा सकता है। 13 के समूह के बचे लोगों के खिलाफ, संयुक्त आरोप पत्र में उल्लिखित दंड संहिता के अपराधों को भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारी राय में, एक नए मुकदमे की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी 21 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उपरोक्त आरोपों को चल रहे मुकदमे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत आसानी से जोड़ा जा सकता है। अभियुक्त पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जाएगा क्योंकि उन्हें जिरह के उद्देश्य से रायबरेली या लखनऊ में पहले से जांचे गए गवाहों को वापस बुलाने का अधिकार है। लखनऊ में सत्र न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 217 (ए) का उचित सम्मान करेगा ताकि वापस बुलाने के अधिकार का इस तरह से प्रयोग न किया जाए कि मुकदमा अनुचित रूप से आगे बढ़े।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. के. वेणुगोपाल की कुछ दलीलों पर विचार करना बाकी है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्तियों का उपयोग कानून को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 यहाँ नीचे दिया गया हैः

> "142. (1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो

उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित कोई डिक्री या आदेश पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में उस तरीके से लागू किया जा सकता है जो संसद द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है और जब तक उस संबंध में प्रावधान इस तरह से नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें।

(2) संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को, पूरे भारत के क्षेत्र के संबंध में, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, किसी भी दस्तावेज की खोज या उत्पादन, या स्वयं की किसी भी अवमानना की जांच या सजा के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी।

18. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य, 1998 (4) एस. सी. सी. 409 में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसले सहित कई फैसलों का हवाला दिया गया है, जिसमें इस अदालत की एक संविधान पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 142 अदालत को अपने समक्ष लंबित कारण से निपटने के दौरान किसी वादी के मूल अधिकारों की अनदेखी करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है और इसका उपयोग इस अदालत के समक्ष कारण पर लागू मूल कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में अन्य फैसलों का भी हवाला दिया गया था। केवल पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह, (2014) 8 एस. सी. सी. 883 में हाल के एक फैसले का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा थाः

"भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 प्रकृति में पूरक है और मूल प्रावधानों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, हालांकि वे क़ानून में

मूल प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो कानून पर समानता को प्राथमिकता देती है। यह कानून की सख्त कठोरता के खिलाफ एक न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को आम तौर पर राहत को ढालने की प्रकृति में और दूसरे को कानून की घोषणा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। "कानून की घोषणा" जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 141 में विचार किया गया हैः देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त या अनिवार्य रूप से निहित भाषण है। यह न्यायालय इंडियन बैंक बनाम एबीएस मरीन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड [(2006) 5 एससीसी 72], राम प्रवेश सिंह बनाम बिहार राज्य [(2006) 8 एससीसी 381:2006 एससीसी (एल एंड एस) 1986] और उत्तर प्रदेश राज्य में है। बनाम नीरज अवस्थी [(2006) 1 एस. सी. सी. 667:2006 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 190] ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाते हुए कहा है कि अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के विपरीत एक बाध्यकारी मिसाल नहीं हैं। वे उचित न्याय करने के लिए जारी किए गए निर्देश हैं और इस तरह की शक्ति का प्रयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के रूप में नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने घोषित कानून के विपरीत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके निर्णय के परिचालन भाग में राहत को विभाजित और अलग किया है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत के निर्देश, राहत को ढालते समय, जो विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कानून के अनुप्रयोग

> में ढील देते हैं या मामले को कानून की कठोरता से छूट देते हैं, अनुपात निर्णय में शामिल नहीं होते हैं और इसलिए इसे एक बाध्यकारी मिसाल बनाने का अपना मूल आधार खो देते हैं। इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 141 को संविधान के अनुच्छेद 141 के दायरे से बाहर रखते हुए और इसे न्यायालय का एक निर्देश घोषित करके संविधान के अनुच्छेद 142 के क्षितिज का विस्तार किया है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विशिष्टता के साथ अपने रंग को बदलता है। [पैरा 12]

19. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) का भारत सरकार अधिनियम, 1935 में कोई समकक्ष नहीं था और हमारी जानकारी के अनुसार, दुनिया भर के किसी भी अन्य संविधान में इसका कोई समकक्ष नहीं है। लैटिन उक्ति फिएट जस्टिटिया रुआट कोएलम वह है जो अनुच्छेद 142 के पढ़ने पर सबसे पहले दिमाग में आता है- न्याय किया जाए, भले ही आकाश गिर जाए। यह अनुच्छेद न्यायालय के समक्ष पक्षों को पूर्ण न्याय करने की बहुत व्यापक शक्ति देता है, एक ऐसी शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद है क्योंकि इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंततः पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को समाप्त कर देगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 142 संविधान के अनुच्छेद 141 का अनुसरण करता है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय के दो घटक होते हैं-घोषित कानून जो व्यक्तियों के बीच भविष्य में मुकदमेबाजी में न्यायालयों को बाध्य करता है, और किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करना जो उसके समक्ष लंबित है। वास्तव में, यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो अपने शीर्ष पर इक्विटी के अधिकतम मानकों में से एक को बदल देता है, अर्थात्, इक्विटी कानून का पालन करती है। अनुच्छेद 142 द्वारा, जैसा कि पंजाब राज्य के फैसले में माना गया है, समानता को

कानून पर प्राथमिकता दी गई है। लेकिन यह उस तरह की समानता नहीं है जो कानून के अनिवार्य मूल प्रावधानों की अवहेलना कर सकती है जब न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करता है। राहत देते समय, न्यायालय पक्षकारों को आवेदन में ढील देने या मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारों को कानून की कठोरता से पूरी तरह से छूट देने की सीमा तक जा सकता है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के पास शक्ति है, नहीं, कर्तव्य है कि वह आवश्यक पाए जाने पर किसी मामले में पूर्ण न्याय करे। वर्तमान मामले में, भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को हिलाने वाले अपराध कथित रूप से लगभग 25 साल पहले किए गए हैं। अभियुक्त व्यक्तियों को मुख्य रूप से एक संयुक्त मुकदमे में उपरोक्त कथित अपराधियों के अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाने में सी. बी. आई. के आचरण और तकनीकी दोषों के कारण कानून के दायरे में नहीं लाया गया है, जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता था, लेकिन जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ठीक नहीं किया गया था। लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं और फिर भी हमें गंभीरता से याद दिलाया जाता है कि अनुच्छेद 142 के तहत पारित किसी भी आदेश से प्रतिवादी संख्या 4 और एस के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि ये अधिकार क्या थे, हमें अंतुले के मामले (ऊपर) के फैसले में इस प्रस्ताव के लिए भेजा गया था कि यदि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के खिलाफ मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है, तो अपील का एक अधिकार छीन लिया जाएगा क्योंकि स्थानांतरण एक मजिस्ट्रेट से सत्र न्यायालय में होगा।

20. यह तर्क उपलब्ध नहीं होता अगर 12 फरवरी, 2001 के फैसले के तुरंत बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद एक और अधिसूचना जारी करके दोष को दूर कर दिया होता। समान रूप से, यदि इस तकनीकी दोष को ठीक करने के लिए राज्य सरकार के इनकार को सी. बी. आई. द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई होती, और दोष को ठीक करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने

के निर्देश को दरकिनार कर दिया जाता, तो लखनऊ में एक संयुक्त मुकदमा अच्छी तरह से चल रहा होता और अब तक समाप्त भी हो चुका होता। तब रायबरेली में सी. बी. आई. द्वारा दायर किए गए किसी भी चयनात्मक पूरक आरोप पत्र की आवश्यकता नहीं होती कि मुकदमे को विभाजित किया जाए। आज हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वह केवल उस सुधार के लिए है जिसकी उम्मीद इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 फरवरी, 2001 के अपने फैसले के तुरंत बाद की गई थी।

21. अंतुले के फैसले में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 7 (1) विचाराधीन थी।

धारा 7 (1) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "7. विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण योग्य मामले-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) या किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 6 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बाड़ की सुनवाई केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।"

22. पैराग्राफ 24 में न्यायाधीश मुखर्जी का बहुमत निर्णय इस धारा का विज्ञापन करता है और इस तथ्य पर जोर देता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद केवल विशेष न्यायाधीशों को ही कुछ अपराधों का मुकदमा चलाना है। वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 (1) में केवल यह कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है और जहां ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, वहां स्थानीय क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय को उसके द्वारा विचारणीय मामले या मामलों के वर्गों का परीक्षण करने की अधिकारिता नहीं होगी। इसकी अनुपस्थिति से धारा 11 में एक गैर-बाध्यकारी खंड स्पष्ट है।

23. पैराग्राफ 34 में, न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि धारा 406 और 407 धारा 7 (1) में गैर-अस्थाई खंड द्वारा कवर किए गए थे। इसका मतलब यह होगा कि धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय धारा 407 (1) के तहत प्रदान किए गए मामले को अपने पास स्थानांतरित नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए विशेष न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार छीन लिया गया है। इसके अलावा, इस कारण से, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 38 में यह कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश से उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कानून द्वारा अधिकृत नहीं है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत पुनरीक्षण या पहली अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार इसलिए छीन लिया गया था। वर्तमान मामले में, यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय को धारा 407 के तहत स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग करना था, उच्च न्यायालय धारा 407 (1) और (8) के तहत रायबरेली और/या लखनऊ में लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित कर सकता था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 (1) के प्रावधान के तहत एक गैर-अस्थाई खंड की अनुपस्थिति इस प्रकार यह स्पष्ट करती है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक अधीनस्थ अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरण भी, जो निस्संदेह अपील का अधिकार छीन लेगा, स्वयं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के तहत 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के रूप में परिकल्पित है।

24. वर्तमान मामले में, स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग एक विशेष न्यायाधीश से दूसरे विशेष न्यायाधीश को मामला स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है, न कि उच्च न्यायालय को। तथ्य यह है कि एक विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट होता है, जबकि दूसरे विशेष न्यायाधीश ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मजिस्ट्रेट से सत्र न्यायालय और

सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत लिया जा सकता है, यानी धारा 407 (1) और (8) के आधार पर, यदि मामले को रायबरेली के मजिस्ट्रेट से ही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए, धारा 407 के तहत, भले ही अपील के 2 स्तरों को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि धारा 407 (8) के साथ पठित धारा 407 (1) (4) द्वारा अपील के अधिकार को छीनने पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाता है। इन परिस्थितियों में, अंतुये का निर्णय, जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 7 (1) में अबाधित खंड के विपरीत स्थानांतरण के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय में एक विशेष न्यायाधीश से एक ठोस अपील के अधिकार से संबंधित था, हमारे सामने तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगा।

25. यह कि अनुच्छेद 142 का उपयोग एक प्रक्रियात्मक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, अर्थात्, एक कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए बहुत अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, श्री वेणुगोपाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 और 407 पर भरोसा किया, जो यहाँ नीचे दी गई हैंः

> "406. मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति-(1) जब भी सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि इस धारा के तहत कोई आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तो वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशेष मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या उच्चतर क्षेत्राधिकार वाले दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित की जाए।

(2) उच्चतम न्यायालय इस धारा के तहत केवल भारत के महान्यायवादी या किसी इच्छुक पक्ष के आवेदन पर ही कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा, जो तब के अलावा जब आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महान्यायवादी हो, शपथ पत्र या पुष्टि द्वारा समर्थित होगा।

(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय, यदि उसकी राय है कि आवेदन तुच्छ या परेशान करने वाला था, तो आवेदक को किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसने आवेदन का विरोध किया है, ऐसी राशि जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं है जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

407. मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति-(1) जब भी उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया जाता है कि (क) उसके अधीनस्थ किसी आपराधिक न्यायालय में निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, या (ख) असामान्य कठिनाई वाले कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है, या (ग) इस संहिता के किसी प्रावधान द्वारा इस धारा के तहत आदेश की आवश्यकता है, या पक्षकारों या गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए है, या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है।

यह आदेश दे सकता है कि (i) किसी भी अपराध की जांच या परीक्षण किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 185 (दोनों

सहित) के तहत योग्य नहीं है, लेकिन अन्य मामलों में ऐसे अपराध की जांच या परीक्षण करने के लिए सक्षम है;

(ii) कि कोई विशेष मामला या अपील, या मामलों या अपीलों का वर्ग, अपने अधिकार के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से समान या उच्चतर अधिकार क्षेत्र वाले किसी अन्य आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए;

(iii) कि कोई विशेष मामला सत्र न्यायालय में परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया जाए; या

(iv) कि किसी विशेष मामले या अपील को स्थानांतरित किया जाए और उसके समक्ष ही मुकदमा चलाया जाए।

(2) उच्च न्यायालय या तो निचली अदालत की रिपोर्ट पर, या किसी इच्छुक पक्ष के आवेदन पर, या अपनी पहल पर कार्य कर सकता हैः

बशर्ते कि किसी मामले को एक आपराधिक न्यायालय से उसी सत्र प्रभाग में दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय में कोई आवेदन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे स्थानांतरण के लिए सत्र न्यायाधीश को कोई आवेदन नहीं किया गया हो और उसके द्वारा खारिज नहीं किया गया हो।

(3) उप-धारा (1) के तहत आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा, जो, जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो, उसके अलावा, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा।

(4) जब ऐसा आवेदन किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उच्च न्यायालय उसे किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए, जो

उच्च न्यायालय उप-धारा (7) के तहत प्रदान कर सकता है, प्रतिभू के साथ या उसके बिना, बांड निष्पादित करने का निर्देश दे सकता है।

(5) ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना, उन आधारों की एक प्रति के साथ देगा जिन पर यह किया गया है और आवेदन के गुण-दोष पर कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी सूचना देने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम चौबीस घंटे नहीं बीत गए हों।

(6) जहां आवेदन किसी मामले के हस्तांतरण या किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपील के लिए है, उच्च न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो आदेश दे सकता है कि आवेदन के निपटारे तक, अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही पर ऐसी शर्तों पर रोक लगाई जाएगी, जो उच्च न्यायालय अधिरोपित करना उचित समझेः बशर्ते कि ऐसी रोक धारा 309 के तहत अधीनस्थ न्यायालय की रिमांड की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

(7) जहां उप-धारा (1) के तहत किसी आदेश के लिए आवेदन खारिज किया जाता है, उच्च न्यायालय, यदि उसकी राय है कि आवेदन तुच्छ या परेशान करने वाला था, तो आवेदक को किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसने आवेदन का विरोध किया है, ऐसी राशि जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं है जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

(8) जब उच्च न्यायालय उप-धारा (1) के तहत आदेश देता है कि किसी मामले को किसी भी न्यायालय से उसके समक्ष मुकदमे के लिए स्थानांतरित किया जाए, तो वह ऐसे मुकदमे में उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उस न्यायालय ने देखी होगी यदि मामला इस तरह से स्थानांतरित नहीं किया गया होता।

(9) इस धारा में कुछ भी धारा 197 के तहत सरकार के किसी भी आदेश को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।"

26. श्री वेणुगोपाल के अनुसार, धारा 406 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति केवल एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या उच्चतर अधिकार क्षेत्र के दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरण द्वारा सीमित है। स्पष्ट रूप से धारा 406 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है क्योंकि स्थानांतरण एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में होता है, दोनों एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। यह मामला होने के कारण, हमें उसी उच्च न्यायालय के तहत एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही स्थानांतरित करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने से कुछ भी नहीं रोकता है क्योंकि धारा 406 बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के तहत किया जा सकता है, न कि इस न्यायालय द्वारा। एक बार फिर, यह तथ्य कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत स्थानांतरण की एक निश्चित शक्ति दी गई है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने से विचलित नहीं होता है। वर्तमान मामले में, कोई ठोस अनिवार्य प्रावधान नहीं है जो अनुच्छेद 142 का उपयोग करके तोड़ा गया हो। इस मामले में, श्री वेणुगोपाल द्वारा लिए गए दोनों आधार आधारहीन हैं

27. हमें 8 दिसंबर, 2011 का उच्च न्यायालय का एक निर्णय दिखाया गया है, जिसमें रायबरेली में चल रहे मामले को समाप्त होने तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ाया जाना था; हमें बताया गया है कि उल्लंघन में इसका केवल पालन किया गया है क्योंकि अभी तक सौ से कम गवाहों से पूछताछ की गई है। सी. बी. आई. के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी कई स्थगन लिए गए। एक अन्य परेशान करने वाली विशेषता यह है कि रायबरेली में मुकदमा चलाने के लिए अधिसूचना द्वारा नामित विशेष न्यायाधीश का कई बार तबादला किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मामले को निर्धारित तिथियों पर नहीं उठाया जा सका। यह मामला होने के कारण, सी. बी. आई. की अपील को स्वीकार करते हुए और विवादित फैसले को दरकिनार करते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

i. कार्यवाही अर्थात। रायबरेली में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपराध संख्या 198/92, RC. 1 (S)/92/SIC-IV/ND को लखनऊ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अयोध्या मामले) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ii. सत्र न्यायालय श्री एल. के. आडवाणी, श्री विनय कटियार, सुश्री उमा भारती, सुश्री साध्वी ऋतंभरा, श्री मुरली मनोहर जोशी और श्री विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ धारा 120-बी के तहत अतिरिक्त आरोप तय करेगा। सत्र न्यायालय श्री चंपत राय बंसल, श्री सतीश प्रधान, श्री धरम दास, श्री महंत नृत्य गोपाल दास, श्री राम बिलास वडंती और श्री वैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम के खिलाफ सी . बी. आई. द्वारा दायर संयुक्त आरोप पत्र में उल्लिखित दंड संहिता की धारा 120-बी और अन्य प्रावधानों के तहत अतिरिक्त आरोप तय करेगा। श्री कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत प्रतिरक्षा के हकदार हैं, जब तक कि वे राजस्थान के राज्यपाल हैं। जैसे ही वे राज्यपाल पद से हटेंगे, सत्र न्यायालय उनके खिलाफ आरोप तय करेगा और उनके खिलाफ कदम उठाएगा।

iii) सत्र न्यायालय, रायबरेली से लखनऊ को कार्यवाही स्थानांतरित करने और अतिरिक्त आरोप तय करने के बाद, चार सप्ताह के भीतर, सभी मामलों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर उस स्तर से उठाएगा, जिस पर रायबरेली और लखनऊ दोनों में मुकदमे की कार्यवाही चल रही है, जब तक कि मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता। कोई नया परीक्षण नहीं होगा। जब तक पूरा मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता तब तक मुकदमे का संचालन करने वाले न्यायाधीश का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। मामला किसी भी आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि जब सत्र न्यायालय उस विशेष तिथि के लिए मुकदमे को जारी रखना असंभव पाता है. ऐसी घटना में, अगले दिन या निकटवर्ती तिथि तक स्थगन के अनुदान पर, इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

iv. सी. बी. आई. यह सुनिश्चित करेगी कि साक्ष्य के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह उपस्थित रहें, ताकि गवाहों की कमी के कारण मामला स्थगित न किया जाए। .

v. सत्र न्यायालय मुकदमा पूरा करेगा और इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर निर्णय देगा।

vi. हम यह स्पष्ट करते हैं कि सत्र न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्ष को स्वतंत्रता दी गई है कि वे इन निर्देशों को अक्षर और भाव दोनों में लागू नहीं किए जाने की स्थिति में हमसे संपर्क कर सकते हैं।

28. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।